www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 98 | जौनपुर शुक्रवार, 21 नवम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

जयशंकर के साथ वार्ता को लेकर बहुत उत्सुक हूं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री

नई दिल्ली, (एजेंसी)। यह यात्रा भारत–ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।" जायसवाल ने वोंग के दिल्ली पहुंचने की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ 16वीं ''विदेश मंत्री फ्रेमवर्क वार्ता'' की सह–अध्यक्षता करने के लिए बुधवार शाम यहां पहुंचीं। वॉन्ग ने कहा कि वह जयशंकर के साथ "और भी महत्वाकांक्षी, भविष्य पर केंद्रित एजेंडे" पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री बृहस्पतिवार को यहां हैदराबाद हाउस में जयशंकर से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग का नयी दिल्ली आगमन पर हार्दिक स्वागत है, जहां वह विदेश मंत्री एस.जयशंकर के साथ 16वीं ''विदेश मंत्री फ्रेमवर्क वार्ता'' की सह–अध्यक्षता करेंगी। यह यात्रा भारत–ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।" जायसवाल ने वोंग के दिल्ली पहुंचने की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।

फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद में और ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह शपथ पत्र दिया है कि इस मस्जिद में और ध्वस्तीकरण की जरूरत नहीं है। इसके साथ अदालत ने मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत मस्जिद की चाहरदीवारी के चिन्हीकरण के लिए आवेदन करने की छूट दी। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन किया जाता है तो आवेदन करने की तिथि से निर्धारित अवधि के अंदर चिन्हीकरण किया जाएगा। फतेहपुर के ललौली गांव में स्थित नूरी जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने यह आशंका व्यक्त की थी कि 19वीं सदी का यह ढांचा ढहा दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने राज्य सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि ध वस्तीकरण की कार्रवाई का निर्देश केवल अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया था। उन्होंने कहा कि जमीन पर जो भी अतिक्रमण था, उसे पहले ही हटा दिया गया है।

10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश

पटना, (एजेंसी)। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस बार उनकी टीम में 26 खिलाड़ी हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और विजय चौधरी जैस दिग्गज नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि, कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में 12 नाम ऐसे भी हैं, जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचेंगे। इसके साथ ही, कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में उपस्थित होंगे। गांधी मैदान पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम हाल के कुछ सालों में सबसे बड़ी राजनीतिक सभाओं में से एक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में तीन लाख से अधिक

लोगों के जुटने की संभावना है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है, निगरानी कैमरे लगाए गए हैं और आपातकालीन चिकित्सा इकाइयों को स्टैंडबाय पर रखा गया है, ताकि समारोह के सुचारू रूप से आयोजन को सुनिश्चित किया जा सके। बुधवार को, नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को निवर्तमान मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर चार दशकों का है। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1985 में जनता दल से हुई थी। , जब उन्होंने पहली बार विध ानसभा चुनाव जीता। शुरुआती वर्षों में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर काम किया। जब 1989 में लालू प्रसाद विपक्ष के नेता बने थे, लेकिन धीरे–धीरे मनमुटाव के कारण नीतीश कुमार और उनकी साझेदारी टूट गई। 1994 में, नीतीश ने लालू प्रसाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह में भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने हर कदम पर किसानों का कल्याण सुनिश्चित किया : सीएम भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, (एजेंसी)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के किसानों पर हाल ही में आई असाधारण बेमौसम बरसात की विपदा से हुए नुकसान से उन्हें उबारने के लिए इस डबल इंजन सरकार ने बहुत ही तेजी से 10 हजार करोड़ रुपए का उदारतम सहायता पैकेज दिया है। मुख्यमंत्री ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर से देश के किसानों के लिए पीएम–किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने के अवसर पर गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कही। इस मौके पर राज्य के किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 21वीं किस्त के अंतर्गत 18 हजार करोड़ रुपए

की सहायता राशि हस्तांतरित की। इस सहायता के तहत गुजरात के 49.31 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए 986 करोड़ रुपए मिले। गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी और कृषि राज्य मंत्री रमेशभाई कटारा ने पीएम–किसान सम्मान निधि के साथ ही 11.68 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न कृषि सहायता के मंजूरी पत्रों का वितरण किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।

नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर धर्मेंद्र प्रधान ने दी बधाई

पटना, (एजेंसी)। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसके बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुने जाने की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा तथा नीतीश कुमार के अनुभवी और सक्षम नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। आगामी वर्षों में यह सुदृढ़ नेतृत्व बिहार को समृद्धि, स्थिरता और सामाजिक न्याय की नई ऊंचाइयों पर अग्रसर करते हुए श्विकसित बिहारश् के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। एनडीए के प्रति अपार विश्वास और अभूतपूर्व समर्थन के लिए बिहार की जनता का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले भाजपा और जदयू के विधायक दल की अलग–अलग बैठक हुई थी। भाजपा की बैठक में जहां सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया, वहीं नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना गया। पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसे लेकर गांधी मैदान में व्यापक तैयारी चल रही है। इस समारोह में आम से लेकर खास लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है। एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा लिया था। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली थी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की।

योगी सरकार के प्रयास से साल दर साल समृद्ध हो रहे यूपी के अन्नदाता

लखनऊ, (संवाददाता)। योगी सरकार के प्रयास से उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसान साल दर साल समृद्ध हो रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि में सहायक बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक तरफ जहां क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से तेजी से धान खरीद हो रही है, वहीं योगी सरकार की नियमित मॉनीटरिंग से किसानों को समय से भुगतान भी किया जा रहा है। विपणन सत्र 2025–26 के तहत बुधवार तक 70 हजार से अधिक किसानों से 4.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक की ध ान खरीद की गई। इस एवज में ध

ान किसानों को अब तक 852.24 करोड़ रुपए भुगतान भी कर दिया गया। यही नहीं, बाजरा के किसानों को भी बुधवार तक 168.39 करोड़ का भुगतान उनके खाते में किया गया। किसानों के हित में योगी सरकार साल दर साल अपने प्रयासों में वृद्धि कर रही है। योगी सरकार के निर्देश पर किसानों को 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। धान किसानों को किए गए भुगतान का आंकड़ा देखें, तो सत्र 2024–25 (19 नवंबर) तक 848.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। वहीं, 19 नवंबर 2025–26 में यह आंकड़ा 852.24 करोड़ रुपए पहुंच गया। खाद्य व रसद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष अब तक 70 हजार से अधिक किसानों से 4.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद की जा चुकी है। इस वर्ष सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बिक्री के लिए अब तक 4,40,318 किसानों ने पंजीकरण भी करा लिया है। धान खरीद के लिए 4171 क्रय केंद्र भी स्थापित कर लिए गए हैं। श्रीअन्न को बढ़ावा देने वाली डबल इंजन सरकार की नीतियां किसानों के लिए कारगर बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। बाजरा किसानों को भी भुगतान समय पर किया जा रहा है।

पीएम मोदी ने पांच बार झुककर किया अभिवादन

पटना , (एजेंसी)। बिहार में आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित इस समारोह को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की तरह भी देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा भाजपा–एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। समारोह के अंत में पीएम मोदी का खास अंदाज भी दिखा। समारोह के दौरान सभी नेताओं ने प्रध ानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की और बिहार की नई सरकार को शुभकामनाएं दीं शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सबसे पहले

वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ थामकर मंच के आगे की ओर बढ़े। इसके बाद पीएम मोदी ने पांच बार झुककर जनता का अभिवादन किया। मंच पर मौजूद शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों के पास जाकर उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया और फिर जनता की ओर मुड़कर अपना गमछा लहराया। बदले में गांधी मैदान में मौजूद लोगों ने भी अपना अपना गमछा लहराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार ऐसा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जब वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, तब भी उन्होंने गमछा लहराकर जनता का अभिनंदन किया था। शपथ ग्रहण समारोह में देशभर से कई बड़े नेता पटना पहुंचे और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी मौजूद थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कई केंद्रीय नेताओं जैसे गिरिराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल, रविशंकर प्रसाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

अदालत बिल मंजूरी की टाइमलाइन तय नहीं कर सकती : राष्ट्रपति

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति के उस संदर्भ पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें पूछा गया था कि क्या कोई सांविधानिक अदालत, राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय–सीमा तय कर सकती है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की संविधान पीठ ने 10 दिनों तक दलीलें सुनीं और 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को राज्य विधानसभा से पारित विध ेयकों पर अनुमोदन देने के लिए न्यायपालिका कोई समयसीमा तय नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने राष्ट्रपति की तरफ से अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए 14 संवैधानिक प्रश्नों पर अपनी राय देते हुए कहा कि यह विषय संवैधानिक पदाधिकारियों के विवेक और संघीय ढांचे की

मर्यादा से जुड़ा है। अदालत ने माना कि विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका श्संवैधानिक कर्तव्यश है, पर न्यायिक हस्तक्षेप के जरिए इसकी समय सीमा तय नहीं की जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि अत्यधिक देरी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा को क्षति पहुंचाती है, इसलिए इन पदों से अपेक्षा है कि वे उचित समय के भीतर निर्णय लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या न्यायालय यह तय कर सकता है।

ममता बनर्जी ने एसआईआर दबाव को ठहराया जिम्मेदार

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर फिर से करारा प्रहार किया है। बुधवार को उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दबाव में मौत हुई। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर एक लंबा पोस्ट लिखकर जलपाईगुड़ी जिले के माल ब्लॉक में एक आंगनवाड़ी वर्कर सह बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की खुदकुशी

पर गहरा दुख जताया। उन्होंने इसे श्चुनाव आयोग की अमानवीय नीतिश का नतीजा बताया। ममता बनर्जी ने पोस्ट कर लिखा, ष्आज फिर एक और कीमती जान चली गई। जलपाईगुड़ी के माल में एक आंगनवाड़ी वर्कर ने एसआईआर के भयानक दबाव में अपनी जान दे दी। एसआईआर शुरू होने के बाद अब तक 28 लोग मर चुके हैं, जिनमें कुछ डर और अनिश्चितता से, तो कुछ तनाव और ओवरवर्क से।ष उन्होंने लिखा, पहले जो काम तीन साल में होता था, उसे चुनाव से ठीक पहले दो महीने में पूरा करने का आदेश देकर राजनीतिक आकाओं को खुश किया जा रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि बीएलओ पर अमानवीय बोझ पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने भारतीय निर्वाचन आयोग से एसआईआर रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ष्मैं ईसीआई से अपील करती हूं कि समझदारी दिखाएं और यह बिना प्लान वाला काम तुरंत रोकें, वरना और जानें जाएंगी। जलपाईगुड़ी के माल ब्लॉक के अंतर्गत लतागुड़ी ग्राम पंचायत की आंगनवाड़ी वर्कर रीना रॉय (42) मंगलवार रात अपने घर में फांसी पर लटकी मिलीं।

ऐतिहासिक पल बिहार एनडीए में नई सरकार का गठन : चिराग पासवान

बिहार, (एजेंसी)। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर चिराग पासवान और अन्य नेताओं ने बिहार पहले, बिहारी पहले के नारे को प्राथमिकता देने की बात कही, जो प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और नीतीश कुमार के अनुभव का लाभ उठाकर, सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने तथा श्विकसित बिहारश् के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर, लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान की माँ रीना पासवान ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह समारोह एक ष्ऐतिहासिक क्षणष है और कहा कि उनके बेटे के नेतृत्व में पार्टी आगे

बढ़ रही है। रीना पासवान ने एएनआई से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। चिराग पासवान ने भी इसी भावना को दोहराते हुए इसे एक बड़ी जिम्मेदारी बताया और कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन और नीतीश कुमार के अनुभव के आधार पर बिहार पहले और बिहारी पहले को प्राथमिकता देगी। पासवान ने कहा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव के साथ बिहार पहले और बिहारियों पहले रखने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने आज गांध ी मैदान में एक भव्य समारोह में शपथ ग्रहण की, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और हजारों समर्थक मौजूद थे। भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास) और कई अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने इस समारोह को ऐतिहासिक बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि बिहार की जनता से मिले प्रचंड जनादेश के बाद नई सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है। नए मंत्रियों ने भी आभार और प्रतिबद्धता व्यक्त की। जदयू की लेशी सिंह ने कहा कि वह बिहार के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करेंगी, जबकि श्रवण कुमार ने विशाल जनादेश के लिए लोगों का धन्यवाद किया और सभी वादों को पूरा करने का वादा किया।

संपादकीय

कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुनीर

नए संशोधन के तहत फील्ड मार्शल असीम मुनीर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन कर सेना के सभी अंगों के प्रमुख बन जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपनी पहल पर मामलों का संज्ञान लेने का अधिकार छीन लिया जाएगा। पाकिस्तान में संविधान संशोधन के जरिए सत्ता का नया ढांचा कायम कर दिया गया है। या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि वहां जो ढांचा व्यवहार में चल रहा था, उसे अब औपचारिक रूप दे दिया गया है। यानी देश में वास्तविक सत्ता निर्वाचित सरकार के हाथ में होने का नकाब उतार फेंका गया है। वैसे हकीकत यही है कि अप्रैल 2022 में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ (पीटीआई) सरकार को सत्ता से हटाए जाने के बाद से असल सत्ता सेना के हाथ में रही है, जिसने शहबाज शरीफ सरकार को अपना श्लोकतांत्रिक मुखौटाय बना रखा है। इमरान खान की सरकार हटाई ही इसलिए गई, क्योंकि उसने संप्रभु अधिकार खुद में होने का भ्रम पाला था। मगर तब सेना को नकाब की जरूरत पड़ी, क्योंकि खान की सरकार को गिराने के क्रम में वह देश में अभूतपूर्व रूप से अलोकप्रिय हो गई। बहरहाल, इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर (पाकिस्तान में बुनयान– अल–मरसूस) के दौरान पाकिस्तानी सेना देश के अंदर अपनी कथित जीत का नैरेटिव बनाने में कामयाब रही। तब से उसका आकलन है कि अब सत्ता पर औपचारिक नियंत्रण बना लेने का सही वक्त है। उस सैन्य कार्रवाई के तुरंत बाद सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बनवाया था। अब नए संशोधन के तहत वे कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन कर सेना के सभी अंगों के प्रमुख बन जाएंगे। इसके साथ ही संवैधानिक मामलों के लिए अलग से न्यायालय का गठन होगा, जबकि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट से अपनी पहल पर मामलों का संज्ञान लेने का अधिकार छीन लिया जाएगा। पाकिस्तान के सत्ता तंत्र में हमेशा, कम–से–कम रक्षा एवं विदेश नीति संबंधी मामलों में, सेना के पास निर्णायक अधिकार रहे हैं। देशी मामलों में भी उसके आर्थिक एवं अन्य हित व्यवहार में सरकार और न्यायपालिका की पहुंच से बाहर रहे हैं। फिर भी कभी–कभार अदालतें सेना नेतृत्व की मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ मामलों का संज्ञान ले लेती थीं। इमरान खान सरकार ने नीतिगत मामले अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। फील्ड मार्शल मुनीर ने अब ऐसी संभावनाओं पर विराम लगवा दिया है।

भारत की श्रम संहिताएं और महिला श्रमिक

उमा

वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के बीच, भारत की नई श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन घरेलू लचीलेपन को मजबूत करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मौका है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना न केवल मैन्यूफैक्चरिंग या तकनीकी क्षमता का विस्तार, बल्कि समावेशी एवं सुदृढ़ संस्थानों के निर्माण पर भी निर्भर करेगा। सच्ची आत्मनिर्भरता एक ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण में निहित है जहां प्रत्येक नागरिक, विशेषकर महिलाएं, देश की विकास गाथा में सार्थक रूप से भाग ले सकें। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023–24 के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017–18 में 22.0 प्रतिशत से बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गया है। जबकि, इसी अवधि में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई है। ये आंकड़े श्रम बाजार में भागीदारी के मामले में व्याप्त लैंगिक अंतर में आई उल्लेखनीय कमी को दर्शाते हैं तथा व्यापक आर्थिक समावेशन की दिशा में सकारात्मक बदलाव की ओर भी इशारा करते हैं। फिर भी, महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा श्रमबल से बाहर है और जो महिलाएं कार्यरत हैं भी, उनमें से कई उन अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं जहां उन्हें कम वेतन, नौकरी की सीमित सुरक्षा और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कृषि एवं घरेलू काम से लेकर घर–आधारित उद्यमों और गिग प्लेटफॉर्म तक, अनौपचारिक रोजगार अक्सर नाजुक आर्थिक स्थिति और असमानता को मजबूत करता है। इस संदर्भ में, भारत के श्रम कानूनों को हाल ही में चार व्यापक संहिताओं में संहिताबद्ध किया जाना इन कमियों को दूर करने का एक अनूठा मौका है। औपचारिकीकरण, संरक्षण और समान पहुंच पर ध्यान केन्द्रित करके, इन सुधारों का उद्देश्य अपेक्षाकृत अधिक समावेशी और सुदृढ़ श्रम बाजार की नींव रखना है। इस प्रयास में भारत अकेला नहीं है। वियतनाम, इंडोनेशिया, मिस्र और मैक्सिको सहित कई विकासशील देशों ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इनमें मातृत्व संबंधी लाभ का विस्तार करना तथा स्वैच्छिक सहमति, सुरक्षित परिवहन, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, महिला पर्यवेक्षण एवं उत्पीड़न–विरोधी ठोस सुरक्षा जैसे सुरक्षात्मक उपायों के तहत महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देना शामिल है। ऐसे उपाय सिर्फ रोजगार को ही संभव बनाने से जुड़े नहीं हैं, बल्कि इनका जुड़ाव महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता और आर्थिक प्रगति में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने से भी है। अब जबकि भारत आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, एक सच्ची समावेशी एवं न्यायसंगत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए महिलाओं को नीति और श्रम सुधार के केन्द्र में रखना अहम होगा। इन संहिताओं में निहित अनेक प्रावधानों में से कई, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इन सुधारों का उद्देश्य कार्यस्थलों को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, अधिक लचीला और अधिक न्यायसंगत बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं पुरुषों के साथ समान स्तर पर अर्थव्यवस्था में भाग लें और उसका लाभ उठा सकें। वेतन और कामकाज की स्थितियों में लिंग–आधारित भेदभाव की समाप्ति भारत के श्रम सुधार, विशेष रूप से वेतन संहिता (2019) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 का उद्देश्य वेतन तथा कामकाज की स्थितियों में लंबे समय से चले आ रहे और श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को सीधे प्रभावित करने वाले लिंग–आधारित भेदभाव से निपटना है। वेतन संहिता (2019) भर्ती और वेतन में लिंग–आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करके ष्समान कार्य के लिए समान वेतनष के सिद्धांत को सुदृढ़ करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संहिता संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन कवरेज को सार्वभौमिक बनाती है। यह प्रावधान कम वेतन वाले अनौपचारिक पेशों में कार्यरत महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें एक बुनियादी स्तर की आय संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज ढांचे की शुरुआत उचित वेतन के लिए मोल–भाव करने की महिला श्रमिकों की क्षमता को मजबूत करती है और साथ ही वेतन के स्तरों में क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करती है। यह लैंगिक आधार पर वेतन में व्यापक अंतर को दूर करने और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आय संबंधी सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके समानांतर, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 महिलाओं को पारंपरिक रूप से नियत कामकाज के घंटों से परे काम करने की अनुमति देकर उनकी आर्थिक भागीदारी के नए अवसर खोलती है। पूर्व में 1948 के फैक्ट्री अधिनियम के तहत कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली में महिलाओं को काम करने से रोकने संबंधी प्रतिबंध के उलट, इस नए संहिता का उद्देश्य कमाई की क्षमता के संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं के बीच समान अवसर प्रदान करना है।

ट्रिब्यूनल सुधार और राष्ट्रपति संदर्भ संबंधी फैसले सवैधानिक मर्यादा और न्यायिक संयम की मिसाल

नीरज

भारत की संवैधानिक संरचना में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन सदैव एक संवेदनशील विषय रहा है। दो दिनों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दो महत्वपूर्ण फैसलों ने इस संतुलन पर नई बहसों को जन्म दिया है। एक ओर न्यायालय ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराकर संसद और केंद्र सरकार को कठोर संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए संदर्भ पर अपनी राय देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल पर अदालत कोई बाध्यकारी समय–सीमा थोप सकती है। इन दोनों फैसलों को मिलाकर देखें तो न्यायालय ने एक ओर कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की है, जबकि दूसरी ओर अपने अधिकार–क्षेत्र की सीमाएँ भी रेखांकित की हैं। न्यायाधिकरण संबंधी फैसले की बात करें तो 19 नवंबर को दिए गए 137 पृष्ठों के निर्णय में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने साफ कहा है कि संसद पहले से रद्द किए गए प्रावधानों को मामूली बदलावों के साथ दोबारा पेश कर न्यायिक फैसलों को दरकिनार नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सरकार बार–बार उन्हीं प्रावधानों को अध्यादेश और फिर कानून के रूप में लागू करती रही, जिन पर न्यायालय स्पष्ट रूप से ऐतराज जता चुका था। यह प्रवृत्ति विधायी अवहेलना के रूप में व्याख्यायित की गईकृ अर्थात, बिना वास्तविक सुधार किए केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन कर न्यायालय की बात को निष्प्रभावी करने का प्रयास। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संस्थागत मर्यादा को ठोस आधार देता है। न्यायाधिकरण सरकार के अंगों के विरुद्ध भी निर्णय लेते हैंय ऐसे में उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा–शर्तें यदि सरकार के नियंत्रण में हों, तो न्यायिक निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है। न्यायालय ने इस अधिनियम को शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करार देते हुए रद्द कर दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि संसद कानून तो बना सकती है, लेकिन न्यायपालिका की मूलभूत स्वतंत्रता को नियंत्रण में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए संवैधानिक संदर्भ पर आया। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न थाकृ क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति पर यह बाध्यता हो सकती है कि वे किसी बिल पर तय समय–सीमा में निर्णय दें? मुख्य न्यायाधीश गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिंह और ए.एस. चंदुरकर की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय राज्यपालध्राष्ट्रपति पर कोई निर्धारित समय–सीमा नहीं थोप सकता। यह स्पष्ट है कि समय बीतने पर बिल को स्वतः मंजूर मान लेने की अवधारणा असंवैधानिक है, क्योंकि यह कार्यपालिका की भूमिका को न्यायपालिका द्वारा हड़पने जैसा होगा। हाँ, यदि लंबे समय तक अनिश्चित देरी हो, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो, तो न्यायालय सीमित दायरे में यह निर्देश दे सकता है कि राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी निभाएँ, लेकिन यह निर्देश विवेकाधिकार के उपयोग पर टिप्पणी नहीं करेगा। इस फैसले से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि न्यायालय ने स्वयं पर अंकुश लगाते हुए साफ किया कि कार्यपालिका के संवैधानिक अधिकारों में दखल की सीमा तय है। दूसरी बात यह है कि राज्यपालों की ओर से बिलों को महीनों तक रोककर रखने की आलोचना को भी न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और समाधान के रूप में सीमित न्यायिक समीक्षा का दरवाजा खुला रखा है। यह संतुलन स्थापित करना आसान नहीं था। एक ओर राज्योंकृ विशेषकर तमिलनाडु, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने तर्क दिया कि राज्यपालों द्वारा बिलों को रोकना लोकतंत्र–विरोधी है। दूसरी ओर, केंद्र ने कहा कि अदालतें समय–सीमा तय करके कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकतीं। अंततः न्यायालय ने वही रास्ता चुना जो भारतीय संविधान की आत्मा के अनुरूप है यानि संविधान ने समय–सीमा नहीं तय की है, इसलिए अदालत भी इसे तय नहीं करेगी। इन दोनों फैसलों में न्यायालय का स्वर पूरी तरह एक जैसा नहीं है। एक तरफ उसने संसद को तीखी चेतावनी दी, दूसरी तरफ उसने खुद अपनी सीमाओं को स्वीकार किया। यही दोहरी भूमिका भारतीय लोकतंत्र को संतुलित बनाती है। न्यायालय संदेश दे रहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का आघात बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन संविधान में जो अधिकार अन्य अंगों को दिए गए हैं, उन पर न्यायपालिका कब्जा नहीं करेगी। इन फैसलों की समय–सीमा भी रोचक है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। उनके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इन दोनों महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसलों पर गवई और सूर्यकांत दोनों की निर्णायक भूमिका भविष्य की न्यायिक दिशा के संकेत देती हैकृ विशेषकर केंद्रदृराज्य संबंधों और न्यायिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में। बहरहाल, संविधान ने भारत को एक संतुलित संरचना दी हैकृ न्यायपालिका स्वतंत्र हो, कार्यपालिका जिम्मेदार हो और विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी हो। इन दोनों फैसलों ने इस संतुलन को और भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। जहाँ न्यायालय ने संसद को बताया कि वह न्यायिक आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकती, वहीं राज्यपालों और राष्ट्रपति की संवैधानिक गरिमा को भी मान्यता दी, यह कहते हुए कि समय–सीमा थोपना न्यायपालिका के अधिकार–क्षेत्र से बाहर है। इन फैसलों के साथ भारत का लोकतंत्र एक बार फिर यह साबित करता है कि संस्थाएँ तभी मजबूत होती हैं जब वे एक–दूसरे की सीमाओं और स्वतंत्रता का सम्मान करें।

नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार एक नई सुबह की आहट

ललित

नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है और यह बड़ी उपलब्धि एवं परिवर्तन आकस्मिक नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सुनियोजित, कठोर और व्यापक रणनीतियों का परिणाम है। वर्षों से जिस समस्या ने भारत के हृदयस्थल को रक्तरंजित किया था, जिस विचारधारा ने दशकों तक विकास, सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं को बंधक बनाए रखा था, वह अब लगभग समाप्ति की कगार पर पहुँच चुकी है। इसका सबसे बड़ा और हालिया प्रमाण है देश के सबसे खतरनाक, खूंखार और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा का खात्मा, एक ऐसा नाम जिसके आतंक ने न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि पूरे तंत्र को लंबे समय तक चुनौती दी। सुकमा क्षेत्र में जन्मा हिड़मा, सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन–1 का प्रमुख। उसकी मौजूदगी मात्र से बड़े–बड़े हमले अंजाम दिए जाते थे। 2010 का दंतेवाड़ा हो या फिर 2013 का झीरम घाटी हमला, पिछले 20 बरसों में हुए लगभग सभी बड़े नक्सली हमलों के पीछे हिडमा का हाथ माना जाता है। उसने लंबे अरसे तक दंडकारण्य में आतंक का राज कायम रखा। दरभा घाटी नरसंहार तक, सुरक्षा बलों के कई घातक ऑपरेशनों का गुनाहगार हिड़मा रहा। उसकी धमक इतनी थी कि उसके सिर पर 50 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का इनाम घोषित था। लेकिन 18 नवंबर 2025 को सुरक्षा बलों के एक अत्यंत सटीक और साहसपूर्ण अभियान में हिड़मा और उसकी पत्नी राजे सहित छह माओवादी ढेर हुए। मौके से मिली एके–47, पिस्टल, राइफलें और अन्य हथियार यह प्रमाणित करते हैं कि यह ऑपरेशन नक्सलवाद की रीढ़ पर निर्णायक प्रहार है। हिड़मा का अंत प्रतीकात्मक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक ऐसा क्षण है जिसने नक्सली नेटवर्क को हिला कर रख दिया है। लंबे समय से 'लाल गलियारा' कहे जाने वाले क्षेत्र की गतिविधियाँ जिस तेजी से सिकुड़ रही हैं, वह दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर जिस दोहरी रणनीति को अपनाया है, उसने वास्तविक जमीन पर असर दिखाया है। मार्च 2026 तक 'नक्सलमुक्त भारत' अभियान के अंतर्गत इस साल 300 नक्सली मारे गए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए और आत्मसमर्पण किया–यह आँकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद अब अपनी वैचारिक और संगठनात्मक शक्ति खो चुका है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दो दिनों में सैकडों नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना यह दर्शाता है कि नक्सल संगठन अब अपने आधार क्षेत्रों में भी समर्थन खो रहा है, और आदिवासी समाज धीरे–धीरे सरकारी विकास योजनाओं की ओर बढ़ रहा है। इसी परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है हिड़मा का खात्मा, जिसने माओवादी कमान में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है, जिसकी भरपाई उनके लिए आसान नहीं होगी। आतंकवाद की तरह ही नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक, गहरी और जटिल चुनौती रहा है। जिस तरह सीमा पार से आने वाला आतंकवाद देश की शांति, विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बना हुआ था, उसी तरह भीतर से जन्मा नक्सलवाद राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता रहा। दशकों तक यह समस्या न सिर्फ कुछ राज्यों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए चिंता और असुरक्षा का कारण रही। लेकिन अब जिस निर्णायक मोड़ पर देश खड़ा है, वह यह संकेत देता है कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। हाल के वर्षों में लगातार मिल रही सफलताएँ, शीर्ष नक्सली कमांडरों का सफाया, व्यापक आत्मसमर्पण, और प्रभावित क्षेत्रों में तेज विकास–ये सभी इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि देश एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। यह वह सुबह है जो भारत को भय, हिंसा और पिछड़ेपन से मुक्त कर, स्थायी शांति और तेज विकास की ओर ले जाती है। नक्सलवाद की जड़ें स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक–आर्थिक असमानताओं, भूमि अधिकारों और आदिवासी इलाकों की उपेक्षा में थीं। कई क्षेत्रों में विकास की रोशनी नहीं पहुँची थी, सरकारी योजनाएँ कागजों में रह जाती थीं, और स्थानीय समुदाय प्रशासन के प्रति अविश्वास से भरे हुए थे। इस वातावरण

में नक्सली संगठनों को जमीन और जनसमर्थन मिला। उन्होंने वर्ग संघर्ष और हथियारबंद क्रांति के नाम पर हिंसा का मार्ग अपनाया, जंगलों को अपनी ढाल बनाया और आदिवासी युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। धीरे–धीरे यह आंदोलन एक साम्यवादी विचारधारा का रूप लेते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक चुनौती बन गया। लेकिन समय के साथ यह आंदोलन अपनी मूल विचारधारा से हटकर आतंक, वसूली, शोषण और खून–खराबे का अड्डा बन गया। सुरक्षा बलों पर हमले, विकास कार्यों को बाधित करना, पुलों और स्कूलों को उड़ाना, आदिवासियों को ढाल बनाना, और सत्ता हासिल करने की लालसा–यह सब नक्सलवाद की असलियत बन गया। इस मानसिकता ने न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दी, बल्कि हजारों परिवारों को तबाह किया और लाखों लोगों के जीवन को भय से भर दिया। लेकिन मोदी एवं शाह के प्रयासों से न केवल नक्सलवाद के खात्मे की सफल लड़ाई लड़ी गयी बल्कि नक्सल क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को लागू किया गया। सड़क–बिजली–मोबाइल नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में काफी काम हुआ है और इससे भी नक्सलियों की पकड़ कमजोर करने में मदद मिली है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2014 से अभी तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 12 हजार किमी से ज्यादा सड़कें बनी है, बैंकों की हजार से ज्यादा शाखाएं खोली गई है और स्किल डिवेलपमेंट पर काम किया जा रहा है। इन समन्वित प्रयासों से ही नक्सली जड़ से उखड़ेंगे। माड़वी हिड़मा जैसे अत्यंत खूंखार और रणनीतिक दिमाग वाले नेता का मारा जाना, नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ने जैसा है। हिड़मा न सिर्फ नक्सलियों की सैन्य रणनीतियों का प्रमुख दिमाग था, बल्कि उसकी छवि ने वर्षों तक सुरक्षा बलों में चुनौती की भावना जगाई रखी। नक्सलवाद के कमजोर होने में केवल सुरक्षा अभियानों की भूमिका नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण रही है। जब सरकार ने स्पष्ट किया कि देश को "नक्सलवाद मुक्त भारत" बनाना है, तो उसके लिए बहु–स्तरीय रणनीति अपनाई गई। एक ओर सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और सटीक इंटेलिजेंस से मजबूत किया गया, वहीं दूसरी ओर सड़कें, स्कूल, अस्पताल, दूरसंचार और आजीविका कार्यक्रमों द्वारा विकास को तेज किया गया। विकास और सुरक्षा का यह संयुक्त प्रभाव नक्सलवाद की जड़ों को खोखला करने में निर्णायक सिद्ध हुआ है।

कांग्रेस के भविष्य पर मोदी की चिंता

सर्वमित्रा

जीत के बाद श्री मोदी का अभिनंदन मखाने की बड़ी सी माला पहना कर किया गया। ध्यान रहे कि मखाना भी इस बार चुनाव का अहम मुद्दा रहा। अमीरों के लिए जो मखाना सुपर फूड कहा जा रहा है, उसे उपजाने वाले किसानों की जो दुर्दशा है, उसे समझने के लिए राहुल गांधी

मखाना किसानों के साथ तालाब में उतरे थे। लेकिन अब भाजपा यह साबित करने में लगी है कि किसानों ने राहुल नहीं मोदी को चुना है। बिहार में जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में जब जीत का जश्न मनाया तो उसमें फिर उसी प्रतीकात्मक राजनीति को बढ़ावा दिया, जिसके चंगुल में फंसकर जनता अपने ही जीवन से जुड़े बुनियादी मुद्दों की अनदेखी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो गमछा लहराकर अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। गमछा एकदम सतह से जुड़े लोगों की खास पहचान है और केवल बिहार ही नहीं, समूचे भारत में आम आदमी इसका इस्तेमाल करता है। बिहार में एक बार तेजस्वी यादव ने गमछा हिलाया था तो फिर नरेन्द्र मोदी ने इसका महत्व समझ लिया। भाजपा कार्यकर्ता जमीन पर काफी मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोदी युग में भाजपा उद्योगपतियों की चहेती पार्टी बन चुकी है। नरेन्द्र मोदी ने अपने ही नामाक्षर वाले सुनहरे धागों से उकेरे गए नमो–नमो लिखे 10 लाख का सूट पहना था, यह देश को याद होगा ही। इसके बाद मोदी सरकार को सूट–बूट की सरकार कहा गया, तो अब भाजपा को जमीन से जुड़ी पार्टी दिखाने के लिए नरेन्द्र मोदी गमछा लहरा रहे हैं। जीत के बाद श्री मोदी का अभिनंदन मखाने की बड़ी सी माला पहना कर किया गया। ध्यान रहे कि मखाना भी इस बार चुनाव का अहम मुद्दा रहा। अमीरों के लिए जो मखाना सुपर फूड कहा जा रहा है, उसे उपजाने वाले किसानों की जो दुर्दशा है, उसे समझने के लिए राहुल गांधी मखाना किसानों के साथ तालाब में उतरे थे। लेकिन अब भाजपा यह साबित करने में लगी है कि किसानों ने राहुल नहीं मोदी को चुना है। मखाना भी प्रतीकात्मक राजनीति का औजार बन गया है। अपने संबोधन की शुरुआत नरेन्द्र मोदी ने जय छठी मईया कहकर की। ओडिशा जीतने के बाद जय जगन्नाथ से जय छठी मईया का यह सफर भी प्रतीकात्मक राजनीति का सबूत है। छठ पूजा के समय नरेन्द्र मोदी दूसरे घाट और साफ पानी की पोल खुल जाने के कारण अर्घ्य देते हुए वीडियो और तस्वीरें नहीं बनवा पाए थे। लेकिन बिहार चुनाव की जीत ने उन्हें छठी मईया का जयकारा लगाने का मौका दे ही दिया। यह तय बात है कि अगर भाजपा यह चुनाव हारती, तब नरेन्द्र मोदी इसे छठी मईया का आदेश मानकर स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे इस पर कुछ कहते ही नहीं। लेकिन अब उन्हें अपने एक झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया है। अपने संबोधन में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विपक्ष ने छठी मईया का अपमान किया, छठ पूजा को नौटंकी कहा। हालांकि ये बात सरासर झूठ है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा था कि नरेन्द्र मोदी अपने लिए अलग घाट बनवाकर छठ पूजा की नौटंकी कर रहे हैं। इसमें छठ पूजा की अवहेलना या छठी मईया का अपमान नहीं था, बल्कि नरेन्द्र मोदी के दिखावे की पोल खोल रहे थे। खबरों के फैक्ट चेक में भी यह साबित हो चुका है कि राहुल गांधी ने छठी मईया का अपमान नहीं किया था, मगर अब नरेन्द्र मोदी इसी झूठ को सौ बार बोलकर उसे सच साबित करने में लगे हैं। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जंगलराज वालों ने एमवाय का तुष्टिकरण किया। हमारे लिए एमवाय का मतलब महिला और यूथ है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद की राजनीति में एम वाय फार्मूला यानी मुस्लिमों और यादवों के वोटों की मिली जुली ताकत को महत्व दिया गया था। राजद का जनाधार मजबूत होने के पीछे यह एक बड़ा कारण रहा। अब मोदी और भाजपा की मर्जी है कि वे एम वाय का विस्तारीकरण अपने हिसाब से करें। हालांकि मोदी ने जिस तरह महिला और यूथ यानी युवा का जिक्र किया है, उससे यह तो तय हो ही गया है कि 10 हजार रूपए चुनावों के वक्त खाते में डालने का फायदा भाजपा को मिला। अब चुनाव आयोग ने यह बेईमानी होने दी कि एक पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करे और उस पर कोई कार्रवाई न हो, तो विपक्षी चाहे जितने दांव–पेंच चल लें, क्या फर्क पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के जश्न में प्रतीकों के इस्तेमाल और विपक्ष पर तंज कसने के अलावा अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को समर्पित किया। जिससे समझ आता है कि कांग्रेस को लेकर उनका डर अब तक गया नहीं है। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता बने रहेंगे, नरेन्द्र मोदी चौन से अपनी सत्ता का मजा नहीं लूट पाएंगे। नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस के विभाजन की भविष्यवाणी ही कर दी। उन्होंने कहा कि– श्कांग्रेस के नामदार जिस रास्ते पर पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उसके प्रति घोर निराशा और घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है।श पाठक जानते हैं कि राहुल गांधी का सीधा नाम नरेन्द्र मोदी कभी नहीं लेते। कभी शहजादे, कभी नामदार ऐसे ही उन पर निशाना साधते हैं। तो अब राहुल गांधी कांग्रेस को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं, इससे नरेन्द्र मोदी फिक्रमंद हो रहे हैं। अगर वाकई राहुल के कारण कांग्रेस को नुकसान है, तब तो मोदी को खुश होना चाहिए। लेकिन मोदी भी जानते हैं कि राहुल के कारण ही कांग्रेस की ताकत बची है। वर्ना उसे भीतर ही भीतर तोड़ने वालों की कमी नहीं है। राहुल ही ऐसे नेता हैं, जिन्हें मोदी और उनके दोस्त अब तक डरा नहीं पाए हैं। बहरहाल, मोदी ने कहा कि मुझे आशंका है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन होगा। कांग्रेस की राजनीति अब नकारात्मक राजनीति वाली हो गई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रवैये की वजह से अंदर–अंदर ही एक नया गुट उभर सकता है। साथ ही उसके सहयोगी भी अब दूरी बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस के सहयोगियों को भी समझ आ रहा है कि सभी को निगेटिव दिशा में ले जा रही है। कांग्रेस के नामदार खुद और दूसरों को भी डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।श नरेन्द्र मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस का विभाजन होगा तो अब मीडिया भी इसके पिष्टपेषण में लग गया है। भाजपा का समर्थित मीडिया है, तो उसे वही नैरेटिव बनाना होगा जो मोदी चाहते हैं। कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता कांग्रेसियों से ज्यादा भाजपा और मीडिया को होने लगी है। दरअसल इन्हें अल्लामा इकबाल के तराने की पंक्तियां पढ़ने की जरूरत है कि– कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर–ए–जमां हमारा। 28 दिसंबर 1885 को स्थापित कांग्रेस एक नहीं कई बार टूट देख चुकी है और कई बार पार्टी से सारे पद और सुविधाएं हासिल करने वाले लोग सत्ता की खातिर उसे छोड़कर जा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा जैसे नाम हाल की मिसालें हैं। मोदी को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी के ग्रेट ग्रैंड फादर यानी पर–परनाना मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले 1922 में कांग्रेस को तोड़ा था। उन्होंने चितरंजन दास के साथ मिलकर नई पार्टी का गठन किया, जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। इसके बाद, सुभाषचंद्र बोस ने 1939 में अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक के नाम से अलग पार्टी बनाई। जेबी कृपलानी ने 1951 में कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। 1956 में सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया।

सात दिवसीय जंबूरी से बाजारों पर बरसेगी करीब 100 करोड़ की समृद्धि, आ रहे 40 हजार से ज्यादा मेहमान

लखनऊ, (संवाददाता)। स्काउट गाइड की सात दिवसीय राष्ट्रीय जंबूरी के लिए 23 से 29 नवंबर तक शहर में देश भर से 40 हजार से ज्यादा मेहमान आने वाले हैं। इनमें 30 हजार स्काउट गाइड कैडेट तो करीब 10 से 15 हजार अन्य लोग होंगे। सात दिन तक इतनी बड़ी संख्या में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मेहमानों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शुरू हुए काम से ही लखनऊ के बाजार पर 100 करोड़ से ज्यादा की समृद्धि बरसने वाली है। मेहमानों के स्वागत व ठहरने के लिए वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बड़े स्तर पर टेंट सिटी बनाई जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों से 30 हजार से ज्यादा प्रतिभागी, 2000 विदेशी प्रतिभागी, पांच हजार अधिकारी व अन्य स्टाफ भी शामिल हो रहे हैं। कुल संख्या 40 हजार पार होने की उम्मीद है। इनके लिए 4500 से ज्यादा टेंट, 1600 शौचालय, 1600 स्नानागर, 35 हजार लोगों की

क्षमता का एरिना स्टेडियम, 100 बिस्तर का अस्पताल, 15 डिस्पेंसरी बनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, टेंट सिटी व अन्य निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा आसपास के होटल व बाजारों में भी रौनक छाने लगी है। डिफेंस एक्सपो मैदान में नागरिक सुविधाओं के अलावा भव्य जंबूरी मेला भी लगेगा। इसके लिए 100 दुकानों का जंबूरी बाजार बन रहा है। इस बाजार के संचालक पवन गुप्ता ने बताया कि 100 में 85 स्टॉलनुमा दुकानों की बुकिंग हो गई है। शेष 15 की बुकिंग एक–दो दिन में हो जाएगी। फूड कोर्ट में 7000 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। स्टॉल से ही 500 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। भारत स्काउट और गाइड यूपी के अनुसार, 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में राजधानी सहित प्रदेश भर से 8000 बालक और बालिकाएं शामिल होंगे। प्रतिभागियों की उम्र 10 से 25 साल निर्धारित की गई है। मानक के अनुसार, प्रतिभागियों के साथ यूनिट गाइड भी शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों से विद्यार्थियों की प्रतिभागिता के लिए प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजा गया है। डिफेंस एक्सपो मैदान में नागरिक सुविधाओं के अलावा भव्य जंबूरी मेला भी लगेगा। इसके लिए 100 दुकानों का जंबूरी बाजार बन रहा है।

सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर अखिलेश यादव ने जताया शोक

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक जताया है और उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। अखिलेश एक्स पर कहा कि घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुःखद ! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि! बता दें कि मऊ जिले की चर्चित घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक सुधाकर सिंह का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। सुधाकर सिंह का 67 साल की उम्र में निधन हुआ है। शुरुआती जानकारी मिली है कि 17 नवंबर को दिल्ली में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के रिसेप्शन से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें मंगलवार को इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया था। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में गुरुवार सुबह उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली।

संक्षिप्त खबरें

ऑटो सर्विस की दुकान में धमाके से शटर उड़ा, दीवारें गिरी

लखनऊ, (संवाददाता)। श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर क्षेत्र के पटना बाजार स्थित ऑटो सर्विस की दुकान में बुधवार की रात जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि दुकान का शटर टूटकर बाहर गिरा और दीवारें दरक गईं। छत भी क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके की आवाज से क्षेत्र में दहशत फैल गई। बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र के काली मिश्रपुरवा निवासी मोती लाल क्षेत्र मल्हीपुर थाना क्षेत्र के पटना निवासी मुरली गुप्ता के घर में दुकान किराए पर लेकर जायसवाल ऑटो सर्विस की दुकान चलाते हैं। मोतीलाल मंगलवार को दुकान बंद कर घर चले गए थे। इस दौरान बुधवार की रात उनकी दुकान में धमाका हो गया। दुकान के पीछे कमरा लेकर किराए पर रह रहे एटा जिले के निधौली थाना क्षेत्र के नंगला देवा निवासी बंटी, सोरो थाना क्षेत्र के नगला उल्फत निवासी संजय, बुलन्दशहर के पहासू थाना क्षेत्र गनगगढ़ नंगला बंजारा निवासी आकाश ने बताया कि रात लगभग 11 बजे अचानक धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे दुकान में आग फैल गई और पूरे घर में काला धुआं फैल गया। हम लोगों ने पीछे के दरवाजे को तोड़ दिया और भाग कर अपनी जान बचाई। सूचना पर आई मल्हीपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया।

विद्युत सखी कार्यक्रम में नई उपलब्धियां, ग्रामीण महिलाओं ने बढ़ाया आत्मनिर्भरता का उजाला

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लगातार ग्रामीण महिलाओं की आजीविका संवर्धन के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर न केवल उनके स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया गया है, बल्कि उनकी आमदनी में भी व्यापक वृद्धि हुई है।इसी प्रयास का एक सशक्त उदाहरण है विद्युत सखी कार्यक्रम, जिसने वर्ष 2020 में शुरुआत के बाद से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने बिजली बिल वितरण कंपनियों के लिए अब तक 2,400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। बिल कलेक्शन के माध्यम से विद्युत सखियों ने 33.05 करोड़ रुपये से अधिक का कमीशन अर्जित कर यह साबित किया है कि ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होने की अपार क्षमता रखती हैं।जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच कलेक्शन के आधार पर बाराबंकी के रामनगर ब्लॉक की राजश्री शुक्ला सूची में शीर्ष पर रहीं। अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक की सोनी द्विवेदी दूसरे स्थान पर और रामपुर जिले के स्वार ब्लॉक की मिशार जहां तीसरे स्थान पर रहीं। इनके बाद आगरा के खंदौली ब्लॉक की कुसुमलता चौथे, बाराबंकी के फतेहपुर ब्लॉक की लक्ष्मी देवी पांचवें और स्वार ब्लॉक की सविता देवी छठवें नंबर पर रहीं। बागपत की रजनी सातवें, मेरठ के राजपुरा ब्लॉक की संगीता आठवें, बुलंदशहर की गीतारानी नौवें और आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक की विनेश दसवें स्थान पर रहीं।

मुआवजा हड़पने के लिए जमीन पर दिखाया दलितों का कब्जा, सरकार को लगाया करोड़ों का चूना

लखनऊ, (संवाददाता)। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण में बड़ा खेल पकड़ में आया है। लखनऊ के सरोजनीनगर में मुआवजा हड़पने के लिए ग्राम समाज की जमीनों पर दलितों का कब्जा दिखाकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया। रिकॉर्ड में यह हेराफेरी एक्सप्रेसवे के सीमांकन के बाद की गई। राजस्व परिषद ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा 122 बी (4 एफ) के अनुसार, अगर किसी जमीन पर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति वर्ष 2007 से पहले से काबिज है, तो उसे हटाया नहीं जाएगा। इसके बजाय उसे पहले 5 साल के लिए जमीन पर असंक्रमणीय भूमिधर अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद उसे संक्रमणीय भूमिधर अधिकार मिलेगा। हालांकि, कृषि भूमि होने पर यह रकबा 3.5 एकड़ से अधिक नहीं होगा। राजस्व परिषद में सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे मामले पकड़ में आए हैं, जिनमें आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए पहले ग्राम समाज की भूमि का चिह्नांकन किया गया, बाद में उस भूमि पर दलितों का कब्जा दिखाया गया। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, अगर ईमानदारी से जांच होगी तो अकेले सरोजनीनगर तहसील में ही यह घपला 100 करोड़ रुपये से पार जाएगा। वहीं, राजस्व परिषद ने प्रदेश में जमीन अधिग्रहण वाले सभी जिलों में जांच का आदेश देने का निर्णय लिया है, ताकि अगर इस तरह के और भी घपले पकड़ में आ सकें। हां, ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें एक्सप्रेसवे के सीमांकन के बाद पट्टे दिए गए हैं। हम ऐसे मामलों की जांच के आदेश दे रहे हैं।

मुठभेड़ में गोली लगने से गैंगस्टर समेत दो घायल

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के अंबेडकरनगर में दुल्हन के पिता से नोटों से भरा बैग छीनने वाले टप्पेबाजों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगने से दोनों घायल हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके पास से तमंचा, कारतूस, बाइक और 5480 रुपये नकद बरामद हुए हैं। बताते चलें कि जयपुर के रामगढ़ नारायणपुर निवासी हंसराज विश्वकर्मा की बेटी की शादी थी। बरात आजमगढ़ जिले से आई थी। द्वार पूजा के लिए दूल्हे के पिता अन्य घरातियों के साथ बरात के स्वागत के लिए खड़े थे। इसी दौरान एक युवक उनके पास आया। नोटों से भरा बैग उनके हाथ से छीनकर भाग गया। कुछ दूरी पर उसके साथी खड़े थे, जो उसे बाइक में बैठाकर रफूचक्कर हो गए। सूचना पर पुलिस केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी थी। घटनास्थल के पड़ोस में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हो गई थी। फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुराने मामलों की कुंडली खंगाली गई। कई लोगों को उठाकर पूछताछ की गई। इसी बीच बुधवार की रात मुखबिर से सूचना मिली कि शादी में टप्पेबाजी करने वाले आरोपी किसी अन्य घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने किशनपुर का बिरहा के ब्रह्म बाबा स्थान पर घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपियों ने फायरिंग झोंक दी। जवाबी कार्रवाई में जलालपुर के शाहपुर फिरोजपुर निवासी विशाल लाला, कृष्णा के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों वहीं गिर पड़े। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। इस बीच तीसरा साथी कुलदीप अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। घायलों को सीएचसी भियाव ले जाया गहया। वहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। तीसरे साथी की पहचान शाहपुर फिरोजपुर निवासी कुलदीप के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपी विशाल लाला पर आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, जलालपुर, बसखारी थाने में 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह बसखारी थाने का गैंगस्टर भी है।

संक्षिप्त खबरें

यात्रा में दिया एकता का संदेश

लखनऊ, (संवाददाता)। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर बुधवार को मध्य विधानसभा क्षेत्र में एकता यात्रा निकाली गई। यह झंडेवाला पार्क अमीनाबाद से शुरू होकर हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पर समाप्त हुई। तिरंगा लिए और भारत माता की जय नारा लगाते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरदार पटेल के पक्ष में 15 में 14 वोट थे, लेकिन कांग्रेसियों ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तब वे गृह मंत्री बने। सरदार पटेल ने कश्मीर में धारा 370 का विरोध किया था और कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आनंद द्विवेदी ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। यात्रा में रमेश तूफानी, रजनीश गुप्ता, अभिषेक खरे, टिंकू सोनकर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

लखनऊ में 21 से 30 नवंबर तक खादी महोत्सव–2025 का भव्य आयोजन

लखनऊ, (संवाददाता)। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, विशाल खंड–4, गोमतीनगर में 21 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक खादी महोत्सव–2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पारंपरिक हस्तशिल्प, खादी उत्पादों और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस दस दिवसीय महोत्सव में प्रदेश भर से 160 से अधिक खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयाँ अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी।महोत्सव का उद्घाटन 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। उद्घाटन समारोह में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर और सचिव प्रांजल यादव शामिल होंगे। कार्यक्रम का संयोजन खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शिशिर द्वारा किया जा रहा है।इस महोत्सव में परंपरागत खादी उत्पादों के साथ–साथ प्रदेश के कारीगरों और उद्यमियों को मंच प्रदान किया जा रहा है ताकि वे अपने कौशल और उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत कर सकें। कार्यक्रम के दौरान तीन ग्रामोद्योग राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे उत्कृष्ट कार्य कर रहे उद्यमियों को सम्मानित किया जा सके।उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव में चयनित लाभार्थियों को दोना मेकिंग मशीन, पॉपकॉर्न मशीन, हनी बॉक्स जैसे उपकरणों के साथ निःशुल्क टूलकिट भी वितरित की जाएगी। माटी कला बोर्ड द्वारा चयनित लाभार्थियों को विद्युत चालित चाक और पगमिल मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पारंपरिक मृदभांड निर्माण को नई गति मिल सके।खादी महोत्सव–2025 न सिर्फ परंपरा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का मंच बनेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वावलंबन और स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। प्रदेशभर से आने वाले कारीगर, स्वयं सहायता समूह और उद्यमी अपने उत्पादों के माध्यम से स्थानीय कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, वहीं आगंतुकों को खादी और ग्रामोद्योग की विविधता को समझने और खरीदने का अवसर मिलेगा।

झांसी को हराकर लखनऊ सेमीफाइनल में

लखनऊ, (संवाददाता)। मेजबान लखनऊ ने झांसी को आसान मुकाबले में 8–0 से मात देते हुए जमनलाल शर्मा मेमोरियल राज्य सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। गया मुकाबला एकतरफा रहा। शुरुआत से ही लखनऊ के खिलाड़ियों ने दबदबा बनाते हुए प्रतिद्वंद्वी टीम पर हमलों की झड़ी लगा दी, जबकि ओर झांसी के खिलाड़ी दबाव में बिखर गए और वापसी नहीं कर

सके। विजेता टीम से कार्तिक धानुक, रियाज और अकरम ने दो–दो गोल दागे, जबकि कप्तान शिवांशु व अनिकेत एक–एक गोल करने में सफल रहे। प्रतियोगिता के दूसरे क्वार्टर फाइनल में करमपुर का सामना लखीमपुर से हुआ। मुकाबले में स्टार खिलाड़ियों से सजी करमपुर की टीम ने लखीमपुर को ककहरा सिखाते हुए 17–1 के विशाल अंतर से जीत दर्ज की। मैच के दौरान करमपुर से विवेक यादव ने बेहतरीन स्किल का प्रदर्शन करते हुए चार गोल दागे, जबकि कप्तान जॉनसन पाल और प्रिंस यादव ने तीन–तीन गोल किए। इसके अलावा राज व अंशू पाल ने दो–दो और प्रांजल पाल, शिवम यादव व आयुष कनौजिया एक–एक गोल करने में सफल रहे। पराजित टीम से कृष्णा ने एकमात्र गोल किया। प्रतियोगिता के तीसरे मुकाबले में भदोही ने विवेक अकादमी वाराणसी को 4–1 से पराजित किया। विजेता टीम से आदित्य ने दो और राज यादव व अनिकेत ने एक–एक गोल किए। प्रतियोगिता के चौथे क्वार्टर फाइनल में नेहरू स्टेडियम गाजीपुर ने सीतापुर को 3–1 से पराजित किया। मैच के दौरान गाजीपुर से कृष सिंह ने दो और अभिषेक कुमार ने एक गोल किया, जबकि पराजित टीम से अमनदीप एकमात्र गोल करने में सफल रहे।

प्रतियोगिता के अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में करमपुर, भदोही और गाजीपुर की टीमों ने जीत दर्ज की। करमपुर ने लखीमपुर को 17–1, भदोही ने विवेक अकादमी वाराणसी को 4–1 और नेहरू स्टेडियम गाजीपुर ने सीतापुर को 3–1 से पराजित किया। चंद्रभान गुप्त खेल मैदान में खेली जा रही प्रतियोगिता के मेजबान लखनऊ और झांसी के बीच खेला

भांवत गाँव बना ग्रामीण पर्यटन का नया आकर्षण, स्पेन से आए मेहमानों ने देखा असली भारतीय गाँव का सौंदर्य

लखनऊ, (संवाददाता)। मैनपुरी के भांवत गाँव ने स्पेन से आए विदेशी अतिथियों को भारतीय ग्रामीण जीवन की ऐसी झलक दिखाई, जिसे वे लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। ग्रामीण पर्यटन परियोजना के तहत आयोजित इस भ्रमण में फेरेस मरीन सैंड्रा, लूर्दस गिराल्डो रोड्रिग्ज और सिंतिया बेलन बोनीनो ने स्थानीय संस्कृति, कृषि व्यवस्था और परंपराओं को नजदीक से समझा। गाँव के प्रतिनिधि विश्राम सिंह ने मेहमानों को पूरे गाँव का भ्रमण कराया, विभिन्न परिवारों से मिलवाया और पीढ़ियों से चली आ रही कला, शिल्प और ग्रामीण परंपराओं से परिचित कराया।अतिथियों ने पारंपरिक बिलौना विधि से माखन निकालने का अनुभव हासिल किया, मिट्टी के बर्तन बनाने की पारंपरिक कारीगरी को देखा, सिंघाड़ा खेती को करीब से समझा और प्रसिद्ध प्राचीन जखदर महादेव मंदिर पहुंचे, जो स्वयंभू शिवलिंग और 200 वर्ष पुराने पवित्र वृक्ष के लिए जाना जाता है। इस पूरे अनुभव ने विदेशी मेहमानों को ग्रामीण समाज की आत्मीयता, सरलता और सांस्कृतिक विविधता का सजीव एहसास कराया।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, मेहमानों का ठहराव 'रोहित होमस्टे' में कराया गया, जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। यहाँ उन्हें प्राकृतिक परिवेश में स्थानीय भोजन, रहन–सहन और आतिथ्य का वास्तविक अनुभव मिला। भांवत गाँव सारस सर्किट संरक्षण परिदृश्य का हिस्सा है, जहाँ 10 हेक्टेयर का जलाशय स्थित है। यही वजह है कि यह क्षेत्र राज्य पक्षी सारस और कई विदेशी प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना बन चुका है।भांवत गाँव सिंघाड़ा उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र है, जिसकी उपज दिल्ली के आजादपुर मंडी तक भेजी जाती है। गाँव में पर्यटन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दस होमस्टे पंजीकृत किए गए हैं। इन होमस्टे के संचालकों को लखनऊ स्थित मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान में पाँच दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि वे पर्यटकों को बेहतर और व्यवस्थित सेवाएँ दे सकें।ग्रामीण पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता पर बोलते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मैनपुरी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 में जहाँ 18,72,670 पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 20,04,724 हो गई। 2025 की पहली छमाही में ही आंकड़ा 6,92,130 तक पहुँच गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार होमस्टे, फार्मस्टे और स्थानीय सुविधाओं को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को पर्यटन के नए केंद्रों में बदलने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।उन्होंने यह भी बताया कि मैनपुरी के महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के पुनर्जीवन पर 27.35 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च की जा रही है। इसमें जाखौआ गाँव स्थित हनुमान मंदिर, पडरिया गाँव की काली माता मंदिर और अन्य आध्यात्मिक स्थलों का विकास शामिल है।ग्रामीण समुदाय की बढ़ती भागीदारी, स्थानीय आजीविका को सशक्त करने के प्रयास, बेहतर होती पर्यटन सुविधाएँ और संरक्षण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ मिलकर उत्तर प्रदेश को ग्रामीण एवं आध्यात्मिक पर्यटन का उभरता हुआ केंद्र बना रही हैं। आज प्रदेश के ऐसे गाँव विकसित हो रहे हैं जहाँ आने वाले पर्यटकों को संस्कृति, प्रकृति, परंपराओं और आत्मीयता का वास्तविक संगम देखने को मिलता है।

धान और मोटे अनाजों की खरीद की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक मंगलवार को राज्यमंत्री सतीश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में धान और मोटे अनाजों की खरीद, किसानों को भुगतान की स्थिति, क्रय केंद्रों की कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चल रहे विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद, आयुक्त अनामिका सिंह, वित्त नियंत्रक कमलेन्द्र कुमार, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अशोक कुमार पाल सहित धान क्रय संस्थाओं और विपणन शाखा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।समीक्षा के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 4171 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 3360 केंद्रों पर खरीद कार्य शुरू हो गया है। 18 नवंबर 2025 तक कुल 67024 किसानों से 3.95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 4.33 लाख मीट्रिक टन था। किसानों को अब तक लगभग 852 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराया जा चुका है। धान की कुल खरीद के सापेक्ष 79112 मीट्रिक टन धान राइस मिलों को भेज दिया गया है, जबकि 78967 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड चावल केंद्रीय पूल में जमा कराया गया है।

मोटे अनाजों की खरीद में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अब तक 13672 किसानों से 64435 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ढाई गुना से अधिक है। इसके अतिरिक्त 1391 किसानों से 4978 मीट्रिक टन ज्वार तथा 806 किसानों से 3371 मीट्रिक टन मक्का की खरीद की जा चुकी है। किसानों को बाजरा खरीद के एवज में 168.39 करोड़ रुपये, ज्वार के लिए 16.68 करोड़ रुपये तथा मक्का के लिए 7.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ ही राज्यमंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने अधिकारियों को क्रय कार्य में पारदर्शिता, सुगमता और गति सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्रय योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई जाए और उन्हें ई–उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पंजीकरण के ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्यापन की प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिन परिवारों की भूमि संयुक्त रूप से है और कुछ सदस्य बाहर रहते हैं, उनके लिए नामिनी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि धान के सत्यापन और खरीद में कोई बाधा न आए।राज्यमंत्री ने क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी क्रय केंद्र समय से खोले जाएँ और किसानों के बैठने, पेयजल और अन्य जरूरतों की समुचित व्यवस्था की जाए। मंडल और जनपद स्तरीय अधिकारियों को प्रतिदिन क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्रय केंद्र पर दैनिक खरीद बढ़ाते हुए प्रतिदिन कम से कम 200 क्विंटल खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भीड़ को नियंत्रित करने और प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यकतानुसार टोकन व्यवस्था लागू की जाए।बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि मण्डियों में स्थापित क्रय केंद्र मण्डी गेट के निकट ही लगाए जाएं, ताकि किसानों को अतिरिक्त भ्रमण न करना पड़े। राज्यमंत्री ने चेतावनी दी कि धान खरीद में अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित केंद्र प्रभारियों और पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीसीएफ, पीसीयू और यूपीएसएस जैसी क्रय एजेंसियों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर पर नहीं है, इसलिए इन एजेंसियों को दैनिक खरीद बढ़ाने और केंद्र प्रभारियों की उपस्थिति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करनी होगी।बैठक में यह संदेश स्पष्ट रहा कि सरकार किसानों के हित, समयबद्ध भुगतान, सुगम खरीद प्रक्रिया और पारदर्शी व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। विभाग की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि क्रय कार्य सुचारू रूप से चले और अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके।

राम मंदिर में ध्वजारोहण से पहले अयोध्या को मिली बड़ी सौगात,यात्रियों की तकलीफें दूर करने की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हमेशा से आम जनता की छोटी–छोटी परेशानियों को गंभीरता से लिया है।इसका ताजा उदाहरण अयोध्या बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग–27 पर बनाया गया नया वाहन अंडरपास है।राम मंदिर में ध्वजारोहण से पहले एक बड़ी सौगात मिल गई है।करीब 21 करोड़ रुपये की लागत से बना यह अंडरपास अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है।जल्द ही इसके संचालन की अधिकृत घोषणा की जाएगी।इसके निर्माण से लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली बसों को अयोध्या धाम बस अड्डे जाने के लिए बड़ी सहूलियत मिल जाएगी।इसके साथ ही हजारों यात्री और स्थानीय लोग पहले की तुलना में बहुत आसानी से और सुरक्षित तरीके से आवागमन कर सकेंगे।भारतमाला परियोजना के तहत एनएचएआई द्वारा कराए जा रहे अयोध्या बाईपास के सुधार एवं पुनर्वास कार्य के दौरान किमी 137. 100 पर यह वाहन अंडरपास (वीयूपी) बनाया गया है। यह स्थान महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय के ठीक पास है। निर्माण कार्य मेसर्स हार्दिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ईपीसी मोड में पूरा किया है। वर्तमान में केवल फिनिशिंग का काम बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर अंडरपास को पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा।इस अंडरपास के साथ–साथ दो पैदल अंडरपास (पीयूपी), एक बॉक्स कल्वर्ट और एक माइनर ब्रिज भी बनाए गए हैं। इन संरचनाओं से ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के यातायात को सुरक्षित रास्ता मिल गया है। खास तौर पर कृषि वाहन, ट्रैक्टर–ट्रॉली, दोपहिया वाहन, रेहड़ी–ठेले और धीमी गति से चलने वाले वाहनों के लिए अब मुख्य राजमार्ग पर क्रॉस करने की मजबूरी खत्म हो गई है। पहले इस जगह पर कई ओडीआर (अन्य जिला सड़कें) और ग्रामीण सड़कें एनएच–27 को काटती थीं। तेज रफ्तार वाहनों और स्थानीय वाहनों के मिश्रण से आए दिन जाम लगता था और दुर्घटनाएं होती थीं। अब तेज गति वाले वाहन मुख्य कैरिजवे पर निर्बाध रूप से दौड़ सकेंगे, जबकि स्थानीय और धीमी गति के वाहन अंडरपास के जरिए सुरक्षित निकल जाएंगे।इससे न केवल दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी बल्कि यात्रियों का समय भी बचेगा।पैदल यात्रियों के लिए भी अब मुख्य सड़क पर जोखिम भरा क्रॉसिंग करना नहीं पड़ेगा।दो अलग–अलग पैदल अंडरपास बनने से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पूरी सुरक्षा के साथ एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकेंगे। जंक्शन पर लंबा इंतजार, बार–बार रुकना और ईंधन की बर्बादी अब इतिहास हो जाएगी। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और ईंधन बचत के साथ–साथ वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा।आसपास के गांवों से कृषि उत्पाद, दूध, सब्जियां और अन्य माल अब तेजी से बाजार तक पहुंच सकेगा।छोटे–मोटे उद्योगों और बाजारों की कनेक्टिविटी मजबूत होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि फिनिशिंग कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ ही दिनों में सभी काम पूरे कर यह वाहन अंडरपास और पैदल अंडरपास जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि अयोध्या को विकसित भारत के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करेगी।योगी सरकार की हर जंक्शन–हर क्रॉसिंग सुरक्षित की नीति का यह जीता–जागता प्रमाण है।अयोध्या बाईपास पर बना यह नया अंडरपास हजारों लोगों की दैनिक यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के साथ–साथ क्षेत्र के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू अयोध्या के अवनीत सिद्धार्थ ने बताया कि हम अयोध्या में लगातार कार्य करा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सभी को एक सुरक्षित सफर प्रदान करें। इसी दिशा में काम करते हुए अंडरपास का निर्माण कराया गया हैं।

48वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का रामपुर में भव्य शुभारंभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। रामपुर ब्लॉक में आयोजित 48 वीं रामपुर ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ श्री सहदेव इंटर कॉलेज, भोड़ा के मैदान में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डॉ. गोरखनाथ पटेल द्वारा फीता काटकर किया गया। मुख्य अतिथि ने बच्चों के अंदर खेल के प्रति दिखे उत्साह और जोश की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेल से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। बच्चों द्वारा बनाई गई सुंदर रंगोली का भी निरीक्षण किया गया। सबसे सुंदर रंगोली बनाने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी, रामपुर अश्विनी सिंह ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री सहदेव इंटर कॉलेज, भोड़ा के प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षकशिक्षिकाओं के सहयोग से प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ग्राम सभा के ग्राम प्रधान द्वारा भी प्रतिभागी बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। प्राथमिक विद्यालय कबड्डी (बालिका वर्ग) का फाइनल मैच न्याय पंचायत बनिडीह बनाम पृथ्वीपुर के बीच हुआ। प्राथमिक विद्यालय कबड्डी (बालक वर्ग)फाइनल मैच पृथ्वीपुर बनाम नोनारी के बीच हुआ।उच्च प्राथमिक विद्यालय कबड्डी (बालक वर्ग) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया । दौड़ प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय 50 मीटर दौड़ (बालक वर्ग) में अरी के हिमांशु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 50 मीटर दौड़ (बालिका वर्ग) में नैंसी ने प्रथम स्थान, 100 मीटर दौड़ (बालिका वर्ग) में नैंसी ने प्रथम स्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय 100 मीटर दौड़ (बालिका वर्ग) रितु ने प्रथम स्थान, 200 मीटर दौड़ (बालक वर्ग) विजय बनवासी ने प्रथम, 400 मीटर दौड़ (बालक वर्ग) विशाल ने प्रथम 600 मीटर दौड़ (बालक वर्ग) में विपिन पटेल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो–खो, दौड़, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। खेल व्यायाम शिक्षक अमित सोनकर, टीम मैनेजर अनुराग सत्यार्थी, टी.पी.एल. स्पोर्ट्स टीम, सभी टीम कोच एवं अध्यापकों का योगदान सराहनीय रहा। बच्चों ने बढ़–चढ़कर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और उत्कृष्ट खेलभावना का प्रदर्शन किया।

विश्वविद्यालयों की दिशा और दशा में हुआ गुणात्मक बदलाव: डॉ. रसिकेश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एच.आर.डी. विभाग में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉ. रसिकेश ने किया। उन्होंने अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्यपाल के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी पुस्तक "चुनौतियां मुझे पसंद हैं" का उल्लेख करते हुए कहा कि किस प्रकार उन्होंने उच्च शिक्षा में अनेक नवाचार लागू कर विश्वविद्यालयों की दिशा और दशा में गुणात्मक परिवर्तन किया है। मुख्य वक्ता श्रेया सिंह ने राज्यपाल के जीवन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 21 नवम्बर 1941 को गुजरात के मेहसाणा जिले में जन्मी श्रीमती आनंदी बेन पटेल आज महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत और सशक्त रोल मॉडल हैं। उनके संवेदनशील प्रशासन का ही परिणाम है कि राज्य विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक महिला कुलपतियों की नियुक्ति कर उन्होंने महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है। प्राध्यापक अनुपम कुमार ने राज्यपाल के दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि नैक, एनआईआरएफ और क्यूएस रैंकिंग में सुधारे हेतु उनकी प्रेरणा से विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन संभव हुआ है। कार्यक्रम में छात्रा निक्की ने राज्यपाल पर आधारित ऊर्जा से भरपूर कविता का पाठ कर सभी को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त अमृता, युगांत, श्रेया सिंह, अन्नू पांडे और अवंतिका ने भी राज्यपाल के योगदान और कार्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में डॉ. प्रवीण मिश्रा, खुशी सिंह, अमृता, संजना मिश्रा, दिव्यांशु सिंह, निधि सिंह, अन्नू पांडेय, आस्था सिंह सहित एच.आर.डी. विभाग के सभी छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

मेडिकल कालेज द्वारा सरायख्वाजा पुलिस स्टेशन में स्वास्थ्य शिविर आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के प्रधानाचार्य प्रो० आर० बी० कमल के दिशा निर्देश में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो० ए०ए० जाफरी एवं जनरल मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डा० विनोद कुमार' के कुशल मार्ग दर्शन में डा० जितेन्द्र कुमार, सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन विभाग द्वारा स्वयं प्रतिभागकर स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन सरायख्वाजा पुलिस स्टेशन में दिनांक 20 नवम्बर, 2025 को किया गया। 'डा० जितेन्द्र मुख्य वक्ता' के रूप में उपस्थित होकर थाना परिसर में मौजूद थानाध्यक्ष, सिपाहियों एवं अन्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कीं। उन्होंने शुगर (मुधमेह) और बीपी (हाईध्लो ब्लड) से होने वाली जटिलताओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम, खासकर ठंड के दौरान, इन बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए मरोजों को नियमित रूप से अपनी जांच कराते रहना चाहिए तथा समय पर दवाओं का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित लोगों को निम्न महत्वपूर्ण सावधानियाँ अपनाने की सलाह दी– ठंड के मौसम में गर्म कपड़ो का उपयोग करें, शुगर व बीपी के मरीज भोजन में सादगी रखें व ज्यादा तला भुना भोजन न करें, नियमित रूप से शुगर व बीपी की जांच कराते रहें, नियमित व्यायाम या हल्की वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कार्यक्रम के दौरान लगभग 60 लोगो का शुगर एवं बीपी की जांच की गई, जो लोग शुगर, बीपी या अन्य किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित थे, उनके बारे में जानकारी लेते हुए डा० जितेन्द्र ने उन्हें सलाह दी कि वे पास के मेडिकल कालेज ध अस्पताल में जाकर अपनी संपूर्ण जांच अवश्य करवाएँ, ताकि समय रहते उचित उपचार मिल सके। थानाध्यक्ष अमेन्द्र पाण्डेय, वरिष्ठ क्राइम इंस्पेक्टर प्रमोद यादव, उपनिरीक्षक सुनिल कुमार एवं अन्य कर्मचारियों ने डा० जितेन्द्र के द्वारा दी गई उपयोगी जानकारी के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने में अत्यंत लानकारी होते हैं। इस अवसर पर मेडिकल कालेज के डा० ऋषिकेश, डा० अक्षय कुमार सिंह व नर्सिंग अधिकारी सतीश यादव, सहायक कर्मचारी, विपिक यादव सहित वार्ड के एम०बी०बी०एस छात्र/छात्राएं उपस्थित रहें।

25 नवंबर को एक बार फिर रामनगरी बनने जा रही है गौरव पल का इतिहास

अयोध्या। 25 नवंबर को एक बार फिर रामनगरी पर पूरे विश्व के निगाह रहेगी क्योंकि उस दिन रामनगरी राम नगरी गौरव पल का इतिहास बनने जा रही है।क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज रोहण करेंगे।इस बार प्राण प्रतिष्ठा से कहीं अधिक एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। अभी हाल में ही दिल्ली पर हुए आतंकी हमले को देखते हुए 25 नवंबर की कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोर कसर सुरक्षा के विभिन्न एजेंसियां नहीं छोड़ना चाहती।इसके लिए गुरुवार से ही संभावना जताई जा रही थी कि शुक्रवार को देर शाम तक एसपीजी के अधिकारी तथा जवान शहर में डेरा जमा सकते हैं। जल थल नभ से सुरक्षा कर्मियों की पहनी नजर सिर्फ अयोध्या धाम पर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों पर भी रहेगी। सूत्र की माने तो इस बार 300 से अधिक सुरक्षाकर्मी रेड जोन में एक ड्रेस कोड में सुरक्षा संभाले हुए नजर आएंगे। इन 300 सुरक्षा कर्मियों में खासकर एसपीजी के जवानों के अलावा सीआरपीएफ पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ–साथ अन्य बैंक के खुफिया तंत्र तथा पुलिस विभाग के चुनिंदा कर्मी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गुरुवार से ही पुलिस विभाग तथा अन्य विभाग के कर्मी ताना–बाना बनने में लग गए और देर रात से ही खास कर कोतवाली नगर थाना कैंट के साथ–साथ राम जन्मभूमि थाना कोतवाली अयोध्या के सीमा में पढ़ने वाले मोहल्ले कॉलोनी होटल गेस्ट हाउस के साथ–साथ अन्य प्रतिष्ठानों में जाकर पुलिस वहां पर रहने वाले व काम करने वाले कर्मचारी वेरिफिकेशन करने में लगी हुई है। इसके अलावा सुरक्षाकर्मी प्रमुख मंदिरों होटल के साथ–सा द सघन वाहन चेकिंग करने में भी जुटे हैं और संदीप अवस्था में पाए जाने वाले लोगों से पूछताछ कर संतुष्ट होने पर ही होने जाने दे रहे हैं। जानकारों की माने तो 25 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर अभी से दूसरे जिलों से आने वाले सुरक्षाकर्मी व अन्य जवान के साथ–साथ खुफिया तंत्र के अधिकारी व कर्मचारी आमद करने में जुटे हैं। बाहर से आने वाले सुरक्षा कर्मियों व अधिकारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में स्कूल कॉलेज होटल गेस्ट हाउस को भी चिन्हित कर उनके रहने के लिए व्यवस्था भी पूर्ण कर ली गई है साथ ही साथ कुछ कॉलेज को रिजर्व भी रखा गया है।वही अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था बनाए जाने की योजना पर काम शुरू हो गया है।जिले स्तर पर मार्ग पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर बैठकों का दौर है।यातायात व्यवस्था और डायवर्जन को लेकर चार्ट बन गया है।मार्ग के किनारे भवनों की छतों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। झेत्र को जोन, सब जोन सेक्टरों में विभाजित कर मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों की तैनाती होगी।सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस कर्मी लोगों पर नजर रखेंगें।राम जन्मभूमि परिसर (रेड जोन) में कुछ विशेष सुरक्षाकर्मी एक ड्रेस में नजर आएंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल किए गए हैं। बुधवार को आईजी, एसएसपी, एसपी सुरक्षा परिसर और सीआरपीएफ कमांडेंट की मौजूदगी में सभी को एक ड्रेस में परेड करा कर रिहर्सल कराया गया।सुरक्षा के बाबत सभी को दिशा–निर्देश जारी किए गये। वही नाम न छापने की शर्त पर एक पुलिस विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह कार्यक्रम बहुत बड़ा और इस पर विश्व की निगाह टिकी हुई है।इसके लिए सफल बनाना हम सभी का दायित्व है वहीं सुरक्षाकर्मियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए हमारा प्रयास यही है कि नजदीक से नजदीक होटल, रेस्टोरेंट, पेइंग गेस्ट हाउस, कॉलेज में उनको रोका जाए।

पंजाबी सिंगर सजाएंगे बॉलीवुड नाइट लगेगा भोजपुरी तड़का भी- इन्हें बुलाने की है तैयारी

गोरखपुर, (संवाददाता)। रामगढ़ताल स्थित चंपादेवी पार्क में 11 से 13 दिसंबर तक प्रस्तावित गोरखपुर महोत्सव में तीन दिनों तक बॉलीवुड और भोजपुरी गायक महफिल सजाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने पंजाबी सिंगर हनी सिंह, मीका और बादशाह से संपर्क साधा है। वहीं, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह मंच पर भोजपुरी तड़का लगाएंगे और भजन गायिका व बिहार से नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी। समारोह का उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे। समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। गोरखपुर महोत्सव की तैयारी को लेकर बुधवार को आयुक्त सभागार में सांसद रवि किशन की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि 11 जनवरी को पहले दिन बॉलीवुड नाइट होगा। अधिकारियों ने बताया कि इसमें पंजाबी सिंगर हनी सिंह, मीका और बादशाह को बुलाने के लिए बातचीत चल रही है। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह को दूसरे दिन यानी 12 जनवरी को भोजपुरी नाइट में बुलाया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम समापन सत्र में गायिका मैथिली ठाकुर को बुलाने की तैयारी है। सांसद रवि किशन ने बताया कि 17 जनवरी तक शिल्प मेला चलेगा। इसमें स्थानीय कलाकारों, उत्पादों और लुप्त हो रही कला व विधा को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक मंच प्रदान किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को अवसर दिया जाएगा। बैठक में महोत्सव की रूपरेखा और कार्यक्रम संचालन से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा आगंतुकों के लिए पार्किंग, प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और पुलिस तैनाती, चिकित्सा सुविधाओं एवं कंट्रोल रूम की स्थापना, शिल्प मेले के स्टॉल आवंटन और निगरानी पर भी चर्चा की गई। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने कहा कि इस वर्ष महोत्सव को और आकर्षक बनाने के लिए विशेष थीम, आकर्षक पवेलियन, फूड कोर्ट और परिवारों के लिए मनोरंजन के कई नए आयोजन शामिल किए जाएंगे। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, पुलिस अधीक्षक अपराध सुधीर जयसवाल, सीएमओ राजेश झा, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

मतदाता एक ही मतदेय स्थल के लिए गणना प्रपत्र भरकर जमा करें:–अपर जिलाधिकारी

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

अपर जिलाधिकारी न्यायिकध्उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने जनपदवासियों को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के प्रगाढ़ पुरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें बूथ लेबल अधिकारी द्वारा घर–घर जाकर मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए संबंधित मतदाताओं से भरे हुये गणना प्रपत्र प्राप्त किये जा रहे है। उन्होने बताया कि ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभी निर्वाचक नामावली 2025 में एक से अधिक मतदेय स्थल अथवा निर्वाचन क्षेत्र में अंकित है, वह मतदाता एक ही स्थान पर अपना गणना प्रपत्र भरकर बूथ लेबल अधिकारी को उपलब्ध करायें और यदि उनके द्वारा दोनों मतदेय स्थल या विधानसभा क्षेत्र में गणना प्रपत्र भरकर बीएलबो को जमा किया जाता है और यह सिद्व हो जाता है कि उक्त मतदाता द्वारा दो जगह गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ क पास जमा किया है, तो उसके विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें मतदाता को एक वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा, जिसके लिए उक्त मतदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

राज्य स्तरीय सम्मेलन विकसित उत्तर प्रदेश 2047 में अयोध्या से डॉ अम्बिकेश त्रिपाठी ने किया प्रतिभाग

अयोध्या। राज्य स्तरीय सम्मेलन विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम मे जिले से डाक्टर अंबिकेश त्रिपाठी ने प्रतिभाग किया।इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी, योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डी पी सिंह ने किया।कार्यक्रम में विकसित उत्तर प्रदेश /2047 का आधार सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए ग्लोबल सिटीजन का निर्माण करते हुए सभी का भारतीय संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ाव पर विस्तार से चर्चा की गई।राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा, शिक्षा में तकनीकी का उपयोग, खान एकेडमी के सहयोग से रोचक ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मिडिल स्टेज से ही व्यवसायिक शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई।इस मौके पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा महानिदेशक – स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, मोनिका रानी, नीति आयोग के ओएसडी जितेन्द्र वर्मा , वरिष्ठ विशेषज्ञ गुणवत्ता शिक्षा आनन्द कुमार पाण्डेय,एल एल एफ के संस्थापक धीर झिंगरन, यूनिसेफ के सीईओ ऋत्विक पात्रा, सीईओ श्रीमती रुक्मिणी, आईआईटी गांधी नगर, गुजरात के प्रोफेसर मनीष जैन, खान एकेडमी की शुभ्रा मित्तल उपस्थिति रहे।

पांच साल में सबसे कम है नवंबर का तापमान, चार डिग्री तक गिरा पारा

भदोही, (संवाददाता)। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोम सक्रिय होने के कारण दिसंबर वाली कड़ाके की ठंड का अहसास नंवबर में ही होने लगा है। ठंड में बढ़ोतरी होने से इस साल पांच साल का रिकार्ड टूट गया है। 2021 से लेकर 2025 तक 11 से 19 नवंबर के बीच के औसत तापमान पर नजर डालें तो 2025 का नवंबर सबसे ठंडा रहा है। इस साल न्यूनतम तापमान बीते पांच वर्ष के औसत तापमान में चार डिग्री तक कम है। कालीन नगरी ठंड से ठिठुर रही है। गलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते पांच साल में नवंबर 2025 सबसे अब तक सबसे ठंडा रहा है। साल 2021 के अपेक्षा रात का पारा चार डिग्री तक लुढ़का है। दिन में धूप खिल रही है लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सुबह–शाम की ठंड व शीतलहर से लोगों की कंपकंपी छूटने लगी है। 2021, 2022 और 2024 में औसतन न्यूनतम तापमान करीब 15 से 16 डिग्री के बीच रहा है। वहीं 2023 में 16–17 डिग्री रहा है।

सत्यापन पूरा, वेबसाइट पर अपलोड हो रही रिपोर्ट

भदोही, (संवाददाता)। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। जिले में 185 विद्यालयों ने केंद्र बनने के लिए परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसका भौतिक सत्यापन अलग–अलग तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में टीम गठित करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। अब उसे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। परिषद स्तर से ऑनलाइन केंद्रों का निर्धारण होगा। जिले में तीन राजकीय इंटर कॉलेजों सहित 38 राजकीय विद्यालय, 25 वित्तपोषित समेत कुल 193 माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।